

सं.ओ.वि./अम्बाला/48-85/21683.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै० (1) आफिसर इन्चार्ज सेंट्रल सोयल एण्ड वाटर कन्जरवेशन, रिसर्च एण्ड ट्रेनिंग इन्स्टीच्यूट रिसर्च सेंटर, सेक्टर 27, चन्डीगढ़ (2) सीनियर टेक्नीकल असिस्टेंट सेंट्रल सोयल एण्ड वाटर कन्जरवेशन, रिसर्च एण्ड ट्रेनिंग इन्स्टीच्यूट, मन्सा देवी, पोस्ट आफिस मनीमाजरा, जिला अम्बाला, के श्रमिक श्री तरसेम सिंह तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई औद्योगिक विवाद है ;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ;

इसलिए, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुये, हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं. 3(44)84-3-अम, दिनांक 18 अप्रैल, 1984 द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, अम्बाला को विवादग्रस्त या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करते हैं, जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत अथवा सम्बन्धित मामला है :—

क्या श्री तरसेम सिंह की सेवाओं का समाधान न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ?

सं.ओ.वि०/अम्बाला/48-85/21690.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै० (1) आफिसर इन्चार्ज सेंट्रल सोयल एण्ड वाटर कन्जरवेशन रिसर्च एण्ड ट्रेनिंग इन्स्टीच्यूट, रिसर्च सेंटर, सेक्टर 27, चन्डीगढ़, (2) सीनियर टेक्नीकल असिस्टेंट सेंट्रल सोयल एण्ड वाटर कन्जरवेशन, रिसर्च एण्ड ट्रेनिंग इन्स्टीच्यूट रिसर्च फार्म मन्सा देवी, पोस्ट आफिस मनीमाजरा, जिला अम्बाला, के श्रमिक श्री बनारसी दास तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई औद्योगिक विवाद है ;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ;

इसलिए, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुये, हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं. 3(44)84-3अम, दिनांक 18 अप्रैल, 1984 द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, अम्बाला, को विवादग्रस्त या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय के लिये निर्दिष्ट करते हैं, जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत अथवा संबंधित मामला है :—

क्या श्री बनारसी दास की सेवाओं का समाधान न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ?

सं. ओ.वि./फरीदाबाद/174-84/21725.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै.एस० जे० निर्दिष्ट एण्ड फिनिशिंग मिलज प्रा० लि०, 13/7 मथुरा रोड फरीदाबाद, के श्रमिक श्री राम मूरत यादव तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई औद्योगिक विवाद है ;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ;

इस लिये, अब औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुये, हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं. 5415-3अम-68/15254, दिनांक 20 जून, 1968 के साथ पढ़ते हुये अधिसूचना सं. 11495-जी.अम 88-अम 57/11245, दिनांक 7 फरवरी, 1958 द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, फरीदाबाद को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय के लिये निर्दिष्ट करते हैं, जो कि प्रबन्धकों तथा श्रमिकों के बीच या तो विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित मामला है :—

क्या श्री राम मूरत यादव की सेवाओं का समाधान न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ?

सं० ओ० वि०/फरीदाबाद/31-85/21752.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै० रिब्रो लिमिटेड दिल्ली रोड गुडगांव के श्रमिक श्री राम अशीश तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई औद्योगिक विवाद है ;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ;

इसलिये, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुये, हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं० 5415-3अम-68/15254, दिनांक 20 जून, 1968 के साथ पढ़ते हुये अधिसूचना सं. 11495-जी-अम-88-अम/57/11245, दिनांक 7 फरवरी, 1958 द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, फरीदाबाद, को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे संबंधित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय के लिए निर्दिष्ट करते हैं, जो कि प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे संबंधित मामला है ;

क्या श्री राम अशीश की सेवाओं का समाधान न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ?